serial being shown on Doordarshan to bring it to an end on July 31, 1988, the most popular episode has been truncated giving a rude shock to viewers, who according to an official estimate comprise 84 per cent of the viewers;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to complete the serial in accordance with accepted scriptures, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Shri Ramanand Sagar, the producer of this Serial originally proposed to produce the story of Rsimayana upto the coronation of Shri Rama in 52 episodes which was approved by the Government. Since he could not complete the story in 52 episodes, Shri Sagar sought approval for 26 additional episodes which was also agreed to by th$_s$ Government. Therefore, there was no question of the Government cutting short this serial.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Sir. The Producer has been requested to produce further episodes at the earliest which will be scheduled for telecast as soon as available.

पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों के कब्जाधीन आवास

2296. **श्री वीरेन्द्र वर्मा :**
श्री शकील हाशमी :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के जिन सदस्यों को राज्यों में भेज दिया गया है वे अभी तक सरकारी आवास पर अपना कब्जा जमाये हुये हैं ; यदि हां, तो ऐसे मंत्रियों के नाम क्या हैं और उन्होंने कब से अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है; उनके कब्जे से सरकारी आवास को खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही प्रारंभ की गई है ;

(ख) ऐसे भूतपूर्व संसद सदस्य कौन-कौन हैं जो राज्य मंत्रिमंडलों के सदस्य नहीं हैं और जिनके पास दिल्ली में सरकारी आवास हैं;

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो मंत्रिमंडल से बाहर हैं परन्तु मंत्रियों के बंगले अभी भी उनके पास है और उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि जिन विरोधी पार्टियों के व्यक्तियों के पास ऐसे आवास हैं उनसे आवास खाली कराने के लिये कार्यवाही की गयी है जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों को रियायत दे दी गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Central Assistance for flood affected States

2297. SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what has been the loss of life and property due to heavy floods and rains in various parts of the country recently;

(b) the nature of assistance given to each of the affected States by the Central Government; and

(c) whether any Central team has been sent to States to assess the damage caused by the floods?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICUL-

TURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) A statement indicating the State-wise damages due to floods and heavy rains during current monsoon period as reported by the affected States, is given enclosed . *[See* Appendix CXLVII, Annexure No. 99].

(b) Rs. 362.50 lakh to Assam and Rs. 37.50 lakhs to Tripura has been released as Central Share of Margin Money.

(c) No, Sir.

सुपर बाजार के माध्यम से बिक्री

2298. श्री राम नरेश यादव :
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के दृष्टिकोण से सुपर बाजार के माध्यम से वस्तुएं बेचने की व्यवस्था की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जुलाई माह के दौरान जब खुले बाजार में चीनी का मूल्य बढ़ गया था, तब चीनी के भंडार की कमी के करण सुपर बाजार भी चीनी की बिक्री नहीं कर सका ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस प्रकार की कुव्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । सुपर बाजार द्वारा जुलाई, 1988 में लगभग 903 मी० टन चीनी बेची गयी थी, जबकि जून, 1988 में 648 मी० टन, मई में 66 मी० टन तथा अप्रैल, 1988 में 497 मी० टन चीनी बेची गई थी ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Arrears of Employees Provident Fund

2299. SHRI ASHIS SEN:
SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Employees Provident Fund Organisation functioning for the welfare of the employers has detected mounting arrears from both unexempted and exempted establishments; and

(b) if so, what was the quantum of arrears during 1986-87 and 1987-88, in both the cases?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) Yes Sir.

(b) The arrears of Provident Fund Contribution at the end of 1986-87 (31-3-87) and 31-12.87 was as given below:—

	31-3-1987	31-12-1987
	(Rupees in crores)	
Unexempted Establishments	71-97	74-34
Exempted Establishments	98-51	104-13

Subscription to EiPF

2300. SHRI MOHAMMED AMIN Will the Minister of LABOUR b pleased to state:

(a) the steps taken to nab errar employers, both of unexempted an exempted establishments, who d